स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते कदम

अरूण कुमार अग्रहरि[1]; डॉ0 अशेष कुमार उपाध्याय[2]

[1]शोध छात्र अर्थशास्त्र विभाग, सल्तनत बहादुर पी0जी0 कालेज, बदलापुर, जौनपुर

[2]असि0प्रो0, अर्थशास्त्र विभाग सल्तनत बहादुर पी0जी0 कालेज, बदलापुर, जौनपुर

Corresponding Author Email: akagrahari828@gmail.com

सारांश— ''स्वास्थ्य ही है जो वास्तविक धन है, सोने और चाँदी के टुकड़े नहीं है।'' जिस प्रकार से दुनिया में तेजी से आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी देशों की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की तुलना में हम बहुत पीछे है। हम अपनी जीडीपी का 2: भी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च नहीं कर पाते हैं।

भारतीय नागरिकों को अभी तक स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ शिक्षा की तरह नागरिक का वैधानिक अधिकार भी नहीं है। शिक्षा का विषय हमारे संविधान के अनुसार राज्य सरकारों को सौंपा गया है। स्वास्थ्य पर कुल सरकारी व्यय का लगभग दो तिहाई हिस्सा राज्य सरकारों से आता है और बाकी एक तिहाई हिस्सा केन्द्र सरकार उपलब्ध कराती है। इसके अलावा यह भी वास्तविकता है कि भारत सरकार ने व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य आरोग्य केन्द्रों तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत, जैसी सफल योजनाओं से स्वास्थ्य नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। भारत सतत् विकास के 2030 के एजेन्डों पर हस्ताक्षर करने वाला देश भी है, जबकि एक राष्ट्र के रूप में 'सबके लिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध भी है।

आजादी के बाद पिछले 7 दशक में भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान देश में 1,58,417 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों 25743 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 5,624 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नेटवर्क तैयार हुआ है। वर्ष 2018 के बाद से 30,000 से भी अधिक उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाओं को बेहतर बनाते हुए इसे ''हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर' का दर्जा दिया गया है।

भारत में नवजात मृत्युदर का आंकड़ा 1994 में प्रति 1000 बच्चों पर 74 था जो वर्ष 2017 में घटकर 33 हो गया। 1990 में देश की औसत आयु 58 वर्ष थी, जो 2017 में बढ़कर 69 वर्ष हो गयी।

भारत चेचक, टिटनेस, पोलियो और गिनिया कृमि रोग के उन्मूलन में सफल रहा है। साथ ही कुष्ठ रोग, मलेरिया, कालाजार आदि सक्रामक बिमारियों को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। वर्ष 2025 तक टीबी को भी समाप्त करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों में काफी गिरावट आयी है, परन्तु देश के सामने गैर–संक्रामक और जीवन शैली से जुड़ी बिमारियाँ कैंसर, मधुमेह, किडनी, हृदय रोग, मानसिक रोग आदि से निपटने और देशी, सस्ते और नवाचारी उपायों के जरिये सबको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने सम्बन्धी लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में गैर–संक्रामक बिमारियों की हिस्सेदारी 55ण्4: है और जिसके कारण 62: होने वाली मौतों की वजह भी गैर–संक्रामक बीमारियाँ हैं।

I. प्रस्तावना

स्वास्थ्य का सामान्य तात्पर्य मात्र शारीरिक स्वास्थ्य न होकर मानसिक और सामाजिक रूप से स्वास्थ्य होना है। साथ ही जब हम इन सभी स्वास्थ्य स्थितियों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते हैं तो से समग्र स्वास्थ्य देखभाल कहा जाता है। स्वास्थ्य केवल दैहिक बीमारियों से मुक्त होना नहीं है, हमें सर्वांगीण अर्थात् समग्र रूप से स्वस्थ होने की आवश्यकता है। भारत में आयुष्मान भारत अभियान के द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य को कवरेज प्रदान किया जा रहा है। सरकार द्वारा चिकित्सा की सस्ती और परंपरागत चिकित्सा के लिए आयुष को बढ़ावा दिया जा रहा है।

II. आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत सरकार की एक स्वस्थ योजना है, जिसे 23 सितम्बर 2018 को सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया।

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल) कार्ड धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का नकद रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार (लगभग 50 करोड़ लोग) इस योजना के द्वारा लाभान्वित हो सकेंगे। इसके बाद बची आबादी को धीरे–धीरे इस दायरे के अन्तर्गत लाने की योजना है।

बजट आवंटन एवं वास्तविक व्यय :

वर्ष	करोड़ रु0 में		
	बजट अनुमान	संशोधित बजट	वास्तविक व्यय
2018–19	2400	2400	1997.92
2019–20	6400	3200	3200
2020–21	6400	3100	2350.46 13/12/2000 तक

उपरोक्त सारणी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना अथवा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) पर भारत सरकार का बजट आवंटन एवं वास्तविक परिव्यय को दिखाया गया है। वर्ष 2018–19 में 2400 करोड़ रु0 का बजट आवंटित किया गया, परन्तु वास्तविक व्यय 1997–92 करोड़ रु0 किया गया तथा वर्ष 2019–20 के लिए आवंटित राशि 6400 करोड़ बढ़कर हो गयी, परन्तु वास्तविक व्यय 50% अर्थात् 3200 करोड़ रु0 ही रहा था तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 में आवंटित राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अर्थात् 6400 रु0 था एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 के 13 दिसम्बर 2020 तक 2350.46 करोड़ रु0 ही वास्तविक व्यय किया गया था।

III. आत्म निर्भर स्वास्थ्य भारत योजना

आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना बजट में की गयी सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक योजना है। 64,180 करोड़ रुपए लागत की इस योजना के अन्तर्गत अगले छह वर्षों में देश में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने का विशाल लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की सुविधाओं का विकास किया जाएगा, वर्तमान राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि नयी और नये रूपों से सामने आ रही बीमारियों का पता लगाकर उनका इलाज किया जा सके।

IV. मिशन पोषण 2.0 योजना

पोषण के स्तर वितरण तथा परिणामों को सुधारने के लिए पूरक पोषाहार कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय कर दिया जाएगा और मिशन पोषण 2.0 योजना चलाने की बात हो रही है। वर्ष 2021–22 वित्तीय वर्ष के लिए महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय द्वारा 24,435 करोड़ रु0 आवंटित किए गये जो वर्ष 2020–21 के मुकाबले 16.31: करोड़ कर दिया गया। 24,435 करोड़ में सबसे अधिक 20,105 करोड़ की राशि सक्षम ऑगनबाड़ी और मिशन पोषण योजना 20 के लिए आवंटित की गयी है। पोषण 2.0 एक व्यापक योजना है, जिसमें समन्वित बाल विकास योजना किशोरियों के लिए योजना और राष्ट्रीय शिशु गृह कार्यक्रम, पोषण अभियान सभी को सम्मिलित किया गया है।

V. स्वास्थ्य बजट

स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालय के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन दोनों सम्मिलित हैं, व राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और अभिघात रोकथाम नियंत्रण कार्यक्रम हो, इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सरकारी योजना भी जैसे आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना), जननी सुरक्षा योजना व प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (पीएमएएसबीवाई) की घोषणा हो, आदि सभी विभिन्न प्रकार की योजनाऐं व रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की क्षमता को विकसित करने के साथ मौजूदा राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने तथा नई उभरती बीमारियों का पता लगाने और उसके निदान के लिए सर्वोत्तम उपाय किए जा रहे हैं और सार्वजनिक व्यय की राशि में की वृद्धि की जा रही है।

हालांकि महामारी (Covid-19) ने लगभग सभी सामाजिक सेवाओं को प्रभावित किया, फिर भी स्वास्थ्य क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय वर्ष 2019–20 (पूर्व कोविड–19 में 2.73 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2021–22 (बीई) में 4.72 लाख करोड़ रु0 हो गया जो लगभग 73% की वृद्धि है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को वर्ष 2025 तक जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों का बजट व्यय वर्ष 2019–20 में 1.3% के मुकाबले वर्ष 2021–22 में GDP के 2.1% प्रतिशत तक पहुँचा दिया गया है। वर्ष 2021–22 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 64,180 करोड़ रुपए परिव्यय के लिए बजट की घोषणा की गई है, इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बजट 2021–22 ने कोविड–19 टीकाकरण के लिए 35000 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया।

स्वास्थ्य बट आवंटन

वर्ष	**स्वास्थ्य बजट (करोड़ रु0 में)**
2010–11	**22765**

2011–12	24355
2012–13	25133
2013–14	27145
2014–15	30626
2015–16	30626
2016–17	37671
2017–18	51382
2018–19	52954
2019–20	62397
2020–21 (BE)	67112

उपरोक्त तालिकाओं द्वारा वर्ष 2010–11 से वर्ष 2020–21 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाली बजटीय आवंटन को दिखाया गया है, जिसके अध्ययन से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश के जरिये देश के बदलते जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति के प्रति काफी सजगता दिखा रही है और जन समुदाय इस सम्बन्ध में आश्वस्त रहें इसके अलावा, इन्होंने इस तथ्य को भी दर्शाने की कोशिश की है कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए एवं कोविड–19 जैसी महामारी से निपटने के लिए तैयार है।

वर्ष 2011–12 में हमारा स्वास्थ्य बजट 24,355 करोड़ रु0 था जो 2020–21 में (BE) बढ़कर 67112 करोड़ रु0 हो गया।

हमारे देश में कोविड–19 का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को मिला था और दो दिन बाद ही आने वाले बजट में स्वास्थ्य बजट को 4: बढ़ा दिया गया था और पिछले 10 वर्षों की तुलना में 175% की बढ़ोत्तरी हुई है। फिर भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य पर कुल जीडीपी का 2: से भी कम खर्च बना हुआ है, जबकि चीन में कुल जीडीपी का 3.2% अमेरिका में 8.5% और जर्मनी में 9.4% खर्च होता है।

वर्ष 2009–10 में सरकार ने हर व्यक्ति की स्वास्थ्य पर वर्ष भर 621 रु0 खर्च किये थे, जबकि 2017–18 में ये खर्च 166% बढ़कर 1657 रु0 हो गया। अगर इस हिसाब से देखा जाय तो रोज सरकार सिर्फ हर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सिर्फ 4.5 रु0 ही खर्च करती है।

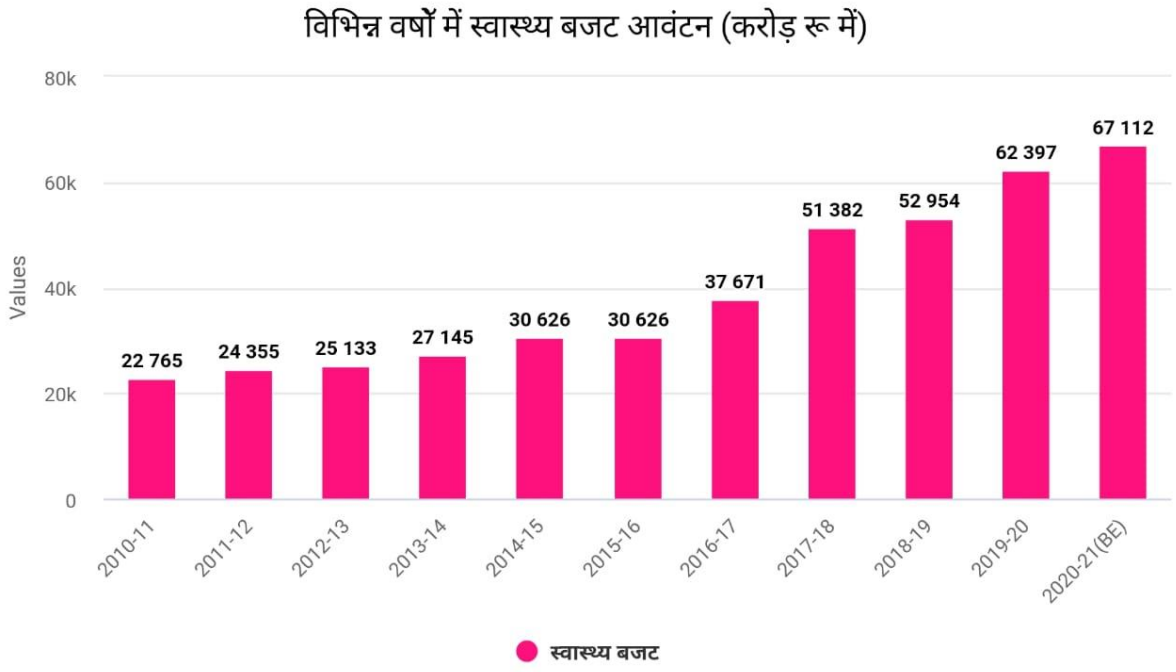

निष्कर्ष–

I. आज भारत डायबटीज का केन्द्र बन गया है ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या मे निरन्तर वृद्धि हो रही है जो हमारी आर्थिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है। भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत योजना प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना मिशन इन्द्र धनुष संचालित हो रहे है। परन्तु मेरी व्यक्तिगत धारणा यह हे कि जब तक लोगों के खान–पान जीवन शैली, पर्यावरण प्रदूषण आदि में सुधार नही किया जाता इन रोगों का इलाज तो करवा सकते है परन्तु बढ़ते रोगियों की संख्या को कम नहीं कर सकते है।

II. निष्कर्ष के रूप में कह सकते है सरकार को सर्वप्रथम स्वास्थ्य शिक्षा की शुल्क भारी भरकम राशि मे कटौती करके स्वास्थ्य शिक्षा को सुलभ बनाना चाहिए। मेडिकल कालेजों व अस्पतालों की संख्या में वृद्धि करना अति आवश्यक है क्योंकि बिना लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के समृद्ध एवं स्वस्थ भारत का निर्माण नही हो सकता है।

III. आज वैश्विक परिदृश्य में बार–बार कोविड–19 महामारी के स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण भी उसके प्रकोप बढ़ने का डर लगा रहता है जिसके सक्रमण को रोकने मे आज भी दुनिया सफल नही हो सकी है इसलिए सामाजिक सेवा के रूप मे स्वास्थ्य पर सरकार को विकसित देशों की भाति बजट परिव्यय को बढ़ाना होगा क्योंकि अभी तक के परिव्यय के अवलोकन से यही चरीतार्थ होता है कि स्वास्थ्य परिव्यय भारत में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए ऊँट के मुँह में जीरा के समान है।

संदर्भ

1. योजना पत्रिका, मई– 2020, पृ0– 18
2. वार्षिक रिपोर्ट 2018–19 से 2021–22, परिवार कल्याण मंत्रालय
3. योजना मार्च–2021, पृ0–02
4. केन्द्रीय बजट 2010 से 2021 (पी0आर0एस0)